

भारत सरकार  
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय  
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1414

जिसका उत्तर 4 दिसंबर, 2024 को दिया जाना है।

13 अग्रहायण, 1946 (शक)

उत्तर प्रदेश में सीएससी

1414. श्री शशांक मणि:

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार के पास उत्तर प्रदेश में वर्तमान में संचालित सामान्य सेवा केन्द्रों (सीएससी) की संख्या के आंकड़े हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी जिला-वार ब्यौरा क्या है और ग्रामीण व्यावसायिक क्रिया-कलापों पर उनका क्या प्रभाव पड़ है; और
- (ख) क्या उत्तर प्रदेश के गांवों में हाई-स्पीड इंटरनेट और मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के साथ-साथ विशेष रूप से महिलाओं और युवाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए ग्रामीण उद्यमियों के लिए डिजिटल प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने की दिशा में प्रगति हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क): सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) ग्राम स्तरीय उद्यमियों (वीएलई) द्वारा स्थापित किए जाते हैं और सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार की एक पहल है, जो इस उद्देश्य के लिए स्थापित एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) है। सीएससी पहल (यानी सीएससी 2.0 परियोजना) का उद्देश्य ग्राम पंचायत स्तर तक नागरिकों को सेवाएं प्रदान करके सरकार को ग्रामीण नागरिकों से जोड़ना है। सीएससी के माध्यम से 800 से अधिक सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, जिनमें सरकारी सेवाएं, वित्तीय सेवाएं और आधार से संबंधित सेवाएं, विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाएं, शिक्षा, टेलीमेडिसिन, यात्रा बुकिंग, उपयोगिता भुगतान आदि शामिल हैं।

सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड ने अवगत कराया है कि दिनांक 31.10.2024 तक उत्तर प्रदेश में कुल 1,21,640 सीएससी (ग्रामीण + शहरी) कार्यात्मक हैं, जिनमें से 95,803 सीएससी ग्राम पंचायत (जीपी) स्तर पर कार्यात्मक हैं। दिनांक 31.10.2024 तक उत्तर प्रदेश राज्यों में कार्यात्मक सीएससी की जिलावार संख्या **अनुबंध-1** में दी गई है।

ये केंद्र ग्राम स्तर के उद्यमियों द्वारा आत्मनिर्भर और उद्यमिता मॉडल पर चलाए जाते हैं। इसके अलावा, सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड द्वारा अवगत कराया गया है कि ये सीएससी उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 3.5 लाख रोजगार (प्रति सीएससी औसतन 3-4 व्यक्ति) प्रदान करते हैं, जिससे आजीविका के बहुमूल्य अवसर पैदा होते हैं। सीएससी ने सरकार से नागरिक (जी2सी) और व्यवसाय से नागरिक (बी2सी) सेवाओं की अंतिम मील तक पहुंच को बढ़ावा देकर कई व्यावसायिक गतिविधियों पर ज़ोर दिया है।

(ख): दूरसंचार विभाग (डीओटी) द्वारा अवगत कराया गया है कि उत्तर प्रदेश के गांवों में हाई स्पीड इंटरनेट और मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने में निम्नानुसार प्रगति हुई है:

- उत्तर प्रदेश में कुल गांव - 1,05,531

- दिनांक 31.10.2024 तक मोबाइल कनेक्टिविटी से कवर किए गए गांवों की कुल संख्या - 1,05,445
- दिनांक 31.10.2024 तक हाई-स्पीड मोबाइल इंटरनेट (3जी/4जी) से कवर किए गए गांवों की कुल संख्या - 1,05,236

सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड ने अवगत कराया है कि एमईआईटीवाई द्वारा शुरू किए गए मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम के तहत वीएलई को 'व्यवहारिक और सॉफ्ट स्किल्स प्रशिक्षण' प्रदान किया है। इसके अलावा यह बताया गया कि दिनांक 31.10.2024 तक 96,000 से अधिक वीएलई प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। इन प्रयासों का उद्देश्य वीएलई को सीएससी को प्रभावी ढंग से संचालित करने और उनकी सेवाओं का विस्तार करने के लिए आवश्यक कौशल से लैस करना है, इस प्रकार महिलाओं और युवाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए ग्रामीण समुदायों में डिजिटल साक्षरता और उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है। विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है।

एमईआईटीवाई ने प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजीदिशा) को भी लागू किया है, जिसे भारत सरकार ने ग्रामीण भारत में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया था। इसका उद्देश्य देशभर में 6 करोड़ ग्रामीण परिवारों (प्रति परिवार एक व्यक्ति) तक पहुँचना था।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) ने अपने 79वें दौर (जुलाई, 2022 से जून, 2023) में 'व्यापक वार्षिक मांड्यूलर सर्वेक्षण' (सीएएमएस) आयोजित किया और उनकी रिपोर्ट के आंकड़ों ने भारत के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता में एक महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रवृत्ति का संकेत दिया। 31 मार्च, 2024 तक देश भर में 6 करोड़ व्यक्तियों के स्थान पर 6.39 करोड़ व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया। उक्त रिपोर्ट से और ग्रामीण क्षेत्रों में स्मार्ट-फोन के उपयोग, इंटरनेट अभिगम और डिजिटल जुड़ाव में उल्लेखनीय वृद्धि को देखते हुए, योजना के उद्देश्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त किया गया है।

उत्तर प्रदेश राज्य में पीएमजीदिशा योजना के तहत कुल 1,63,14,369 उम्मीदवार नामांकित हुए और 1,45,48,273 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया।

\*\*\*\*\*

#### अनुबंध- I

दिनांक 31.10.2024 तक उत्तर प्रदेश में जिलावार क्रियाशील सीएससी		
जिले का नाम	कुल (शहरी + ग्रामीण)	ग्रामीण
आगरा	1,776	1,152
अलीगढ़	1,527	1,050
अंबेडकर नगर	1,506	1,311
अमेठी	1,600	1,518
अमरोहा	1,557	1,211
औरैया	1,090	825
अयोध्या	1,591	1,425
आजमगढ़	2,291	2,052
बागपत	764	554
बहराइच	2,014	1,788
बलिया	1,653	1,441
बलरामपुर	1,197	1,055
बाँदा	908	702
बाराबंकी	1,980	1,738

बरेली	3,187	2,207
बस्ती	1,815	1,653
भदोही	951	813
बिजनौर	2,574	1,981
बदायू	2,050	1,569
बुलंदशहर	2,321	1,695
चंदौली	1,302	1,156
चित्रकूट	561	460
देवरिया	2,197	1,857
एटा	1,235	964
इटवा	1,097	786
फर्रुखाबाद	1,326	986
फतेहपुर	1,204	968
फिरोजाबाद	1,714	1,003
गौतम बुद्ध नगर	807	271
गाजियाबाद	1,395	394
गाजीपुर	1,731	1,547
गोंडा	2,217	2,017
गोरखपुर	2,461	2,058
हमीरपुर	764	544
हापुड़	818	612
हरदोई	2,139	1,819
हाथरस	1,067	775
जालौन	1,036	692
जौनपुर	2,279	2,008
झांसी	1,001	637
कन्नौज	831	625
कानपुर देहात	1,288	1,080
कानपुर नगर	1,567	740
कासगंज	995	732
कौशाम्बी	1,130	971
खेरी	2,031	1,807
कुशीनगर	2,607	2,267
ललितपुर	775	613
लखनऊ	2,596	1,238
महाराजगंज	2,162	1,944
महोबा	684	501
मैनपुरी	1,400	1,020
मथुरा	1,180	756
मऊ	1,218	947
मेरठ	1,778	982
मिर्जापुर	1,390	1,199
मुरादाबाद	2,804	1,893
मुजफ्फरनगर	1,349	1,038
पीलीभीत	1,964	1,616
प्रतापगढ़	2,387	2,165

प्रयागराज	3,418	2,988
रायबरेली	1,682	1,485
रामपुर	2,044	1,580
सहारनपुर	2,802	2,098
संभल	1,872	1,476
संत कबीर नगर	1,148	1,034
शाहजहांपुर	1,989	1,621
शामली	889	599
श्रावस्ती	702	649
सिद्धार्थ नगर	1,980	1,816
सीतापुर	1,965	1,659
सोनभद्र	1,315	1,164
सुल्तानपुर	1,345	1,262
उन्नाव	1,788	1,495
वाराणसी	1,862	1,449
<b>कुल</b>	<b>1,21,640</b>	<b>95,803</b>

स्रोत: सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड

\*\*\*\*\*

मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत वीएलई के प्रशिक्षण की स्थिति			
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	भाग लेने वाले वीएलई की संख्या (पुरुष)	भाग लेने वाले वीएलई की संख्या (महिला)	भाग लेने वाले वीएलई की कुल संख्या
आंध्र प्रदेश	1,094	349	1,443
अरुणाचल प्रदेश	25	2	27
असम	2,277	779	3,056
बिहार	16,362	1,007	17,369
छत्तीसगढ़	3,795	980	4,775
दिल्ली	1	0	1
गुजरात	1,461	129	1,590
हरियाणा	678	63	741
हिमाचल प्रदेश	246	35	281
जम्मू और कश्मीर	1,261	119	1,380
झारखंड	13,243	1,961	15,204
कर्नाटक	1,350	107	1,457
केरल	132	73	205
मध्य प्रदेश	7,039	774	7,813
महाराष्ट्र	9,280	986	10,266
मेघालय	128	48	176
मिजोरम	84	14	98
नागालैंड	31	25	56
ओडिशा	4,688	358	5,046
पंजाब	755	129	884
राजस्थान	3,289	390	3,679
सिक्किम	88	36	124
तमिलनाडु	1,055	351	1,406
तेलंगाना	1,268	307	1,575
त्रिपुरा	284	31	315
उत्तर प्रदेश	10,211	657	10,868
उत्तराखंड	2,153	392	2,545
पश्चिम बंगाल	3,789	300	4,089
<b>कुल योग</b>	<b>86,067</b>	<b>10,402</b>	<b>96,469</b>

स्रोत: सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड

\*\*\*\*\*